



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022024-252115
CG-DL-E-15022024-252115

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 675]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 14, 2024/माघ 25, 1945

No. 675]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 14, 2024/MAGHA 25, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2024

का.आ. 711(अ).—भारत सरकार दिनांक 01.02.2024 को मंत्रिमंडल के अनुमोदन से उर्वरक (यूरिया) संयंत्र उत्पादकों को आपूर्ति की जाने वाली किसी भी घरेलू गैस पर विपणन मार्जिन के निम्नानुसार निर्धारण को एतद्वारा अधिसूचित करती है –

- दिनांक 01.05.2009 से दिनांक 17.11.2015 तक की अवधि के लिए देश के भीतर उत्पादित और उर्वरक (यूरिया) संयंत्र उत्पादकों को आपूर्ति किसी भी घरेलू गैस पर 200 रुपए प्रति 1000 एससीएम (10,000 केसीएएल/एससीएम के एनसीवी की दर से) या वास्तविक विपणन मार्जिन भुगतान/प्रभारित, जो भी कम हो, के विपणन मार्जिन पर अनुमोदन हेतु विचार किया जा सकता है।
- उर्वरक विभाग उन यूरिया संयंत्रों को भुगतान निर्धारित करने के लिए विपणन मार्जिन की उक्त राशि पर विचार करेगा जहां विपणन मार्जिन की राशि को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण राजसहायता भुगतान में विपणन मार्जिन को शामिल नहीं किया गया था।

[फा. सं. एल-16013/1/2019-जीपी-I(ई-45493)]

रमेश कृष्ण, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th February, 2024

S.O. 711(E).—The Government of the India, with the approval of the Cabinet on 01.02.2024, hereby notifies the determination of Marketing Margin on any domestic gas supplied to Fertilizer (Urea) plants producers as under –

- i. Marketing Margin upto ₹ 200 per 1000 SCM (@NCV of 10,000 Kcal/SCM) or actual marketing margin paid/charged, whichever is less, on any domestic gas produced within the country and supplied to Fertilizer (Urea) plants producers may be considered for the period 01.05.2009 to 17.11.2015.
- ii. Department of Fertilizers will consider the said amount of marketing margin for determining the payment to urea plants where marketing margin was not included in the subsidy payment due to non-finalization of the amount of marketing margin.

[F. No. L-16013/1/2019-GP- I(E-45493)]

RAMESH KRISHNA, Under Secy.